प्रदेश को बनाएंगे देश की 'मिल्क कैपिटल'

पशुपालकों के लिए योजनाओं से बदलेगी गांवों की तस्वीर, लाएंगे श्वेत क्रांति : डॉ. मोहन यादव

“ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश एक बार फिर देश में अपना परचम फहराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश का 'फूड बॉस्केट' बनने के बाद अब डॉ. यादव राज्य को भारत की 'मिल्क कैपिटल' बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कई योजनाएं भी मोहन सरकार ने शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य एक ओर जहां दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश की भागीदारी 20% तक पहुंचाना है, वहीं प्रदेश के पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ाना भी है। ”

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि राज्य के पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों को हर संभव तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने सहित वर्तमान डेयरी उद्योग को सुनियोजित, सुव्यवस्थित, व्यावसायिक और लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। हमारा संकल्प है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़े और ग्रामीण स्तर पर श्वेत क्रांति लाकर वर्ष 2028 तक प्रदेश को देश की 'मिल्क कैपिटल' बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि गौ-संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, कामधेनु निवास योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ ही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में न केवल गौवंश का समुचित पालन-पोषण किया जा रहा है, अपितु दुग्ध उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। डॉ. यादव ने बताया कि अब प्रदेश सरकार ने 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना' और 'क्षीर धारा ग्राम योजना' आरंभ की हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में अभी जहां देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9% होता है, उसे 20% तक ले जाना सरकार का लक्ष्य है।

मिल्क कैपिटल के लिए सरकार के प्रयास

- राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2026-27 के अपने बजट में अलग-अलग राशि आवंटित की है। इसमें पशुपालन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 2 हजार 365 करोड़, गौ-संवर्धन एवं पशु संवर्धन योजना के लिए 620 करोड़ 50 लाख एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
- गौवंश के लिए आहार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली राशि को 20 से बढ़कर 40 रुपये किया गया है।
- 'हर घर गोकुल' के लिए 946 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है।
- मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद में एक वृंदावन ग्राम बनाया जा रहा है।
- वर्ष 2030 तक डेयरी नेटवर्क का विस्तार कर 52 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। बढ़े हुए दुग्ध संकलन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित की जाएगी।

Media Marketing Initiative

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ पशुपालन

गाय हमारे लिए माता के समान और पूजनीय है। पशुपालन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश (लगभग 22% वैश्विक उत्पादन) है। यह बात कहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बताया कि डेयरी क्षेत्र के विकास पर हमारी सरकार जोर दे रही है, जिससे देश के 8 करोड़ परिवारों को आजीविका मिल रही है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% से 57% से अधिक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस पशुपालन, डेयरी के विस्तार और गोबरधन (गोबर से धन) पर है। पशुधन (गाय-भैंस) ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार ने 'पशु आरोग्य मेला' और 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' जैसी पहलों के माध्यम से नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में दूध उत्पादन की वार्षिक दर 6% है, जो वैश्विक दर (2%) से कहीं अधिक है और उत्तरप्रदेश देश का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं और छोटे किसानों की आय में वृद्धि करने और गौवंश की देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार अन्य प्रयास भी कर रही है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं।

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग: केंद्र सरकार ने गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है, जो गौ-कल्याण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करता है।

गोबर-धन और बायोगैस को बढ़ावा: पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के माध्यम से गोबर और गौमूत्र के कुशल उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत एनडीडीबी एमआरआईडीए (NDDB MRIDA) लिमिटेड के माध्यम से बायोगैस और जैविक खाद उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

पशुधन बीमा योजना: पशुपालकों को जोखिम से बचाने के लिए सरकार गाय और अन्य पशुओं के लिए बीमा कवर प्रदान करती है, ताकि पशु की मृत्यु होने पर किसान को आर्थिक नुकसान न हो।

गौ-आधारित प्राकृतिक खेती: कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से किसानों को गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग करके जीवामृत, बीजामृत और वर्मी कम्पोस्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

डेयरी गतिविधियों से जोड़ेंगे 26 हजार गांव, मोबाइल ऐप से होगा दुग्ध संकलन

जिला स्तर पर कार्यक्रमों में होगा आदर्श पशुपालकों का सम्मान

राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए डेयरी गतिविधियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के दुग्ध संघों को दिए जा रहे सहयोग से दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है और किसानों को भी दूध के बेहतर दाम मिल रहे हैं। दुग्ध समितियों में महिला सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। डेयरी सहकारी कवरेज के विस्तार और सुदृढ़ीकरण, नई डेयरी प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और पशु चारा संयंत्र के आधुनिकीकरण, डेयरी वैल्यू चैन के डिजिटलाइजेशन, पारदर्शिता और दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। डेयरी विकास योजना के अंतर्गत 26 हजार गांवों को जोड़ने, प्रतिदिन दुग्ध संकलन 52 लाख किलोग्राम तक करने का लक्ष्य रख, गतिविधियां चलाई जाएं। ये निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की राज्यस्तरीय संचालन समिति की बैठक में दिए।

डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श पशुपालकों को सम्मानित करने, दूधारू पशुओं की प्रदर्शनी आयोजित करने और डेयरी के संबंध में सूचना देने जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जाएं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध संघों का कार्यअनुबंध करने के बाद वर्ष 2025-26 में 1752 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन

किया गया तथा 701 निष्क्रिय दुग्ध समितियों को क्रियाशील किया गया है। प्रदेश में प्रतिदिन 9 लाख 67 हजार किग्रा दुग्ध संकलन किया जा रहा है, 153 नवीन बल्क मिल्क कूलर की स्थापना की गई है। प्रदेश में दुग्ध संकलन मोबाइल ऐप द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे दुग्ध प्रदायकों को दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी तत्काल मिल सकेगी। क्षेत्र संचालन तथा विपणन कार्य में लगे मैदानी अमले की मॉनीटरिंग के लिए फील्ड फोर्स मॉनीटरिंग ऐप आरंभ किया गया है। इंदौर में स्थापित 30 मीट्रिक टन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र आरंभ किया जा चुका है। शिवपुरी में 20 हजार लीटर क्षमता के डेयरी संयंत्र और ग्वालियर डेयरी संयंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। पशु आहार संयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए विशेष व्यवस्था लागू की गई है। पीपीपी मोड पर भी प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना पशुपालकों को बनाएगी आत्मनिर्भर

राज्य सरकार की डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना उन युवाओं, किसानों और पशुपालकों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है, जो आधुनिक डेयरी इकाई स्थापित कर अपनी आय का स्थायी साधन विकसित करना चाहते हैं। योजना अंतर्गत 25 दुधारू पशु की प्रति इकाई पर 36 लाख से 42 लाख रुपये तक की लागत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत तथा अन्य वर्गों को 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। योजना में एक हितग्राही अधिकतम 8 इकाई लगा सकता है। एक इकाई में एक ही नस्ल के गौ-वंश या भैंसवंशीय पशु रहेंगे। हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है। भूमि के लिए परिवार के सामूहिक खाते भी मान्य होंगे। हालांकि इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति भी जरूरी होगी। इकाइयों की संख्या बढ़ने पर कृषि भूमि की अर्हता में भी आनुपातिक वृद्धि जरूरी होगी।

इस तरह मिलेगा योजना का लाभ

- पात्र हितग्राही को ऋण राशि का भुगतान चार चरणों में किया जाएगा।
- आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की बढ़ेगी आमदनी

मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच हुआ 5 साल का अनुबंध

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच एक अनुबंध किया है। 5 वर्ष की अवधि के इस अनुबंध का आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा। इसके तहत मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे, दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी और दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन सबके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इस सहकार्यता अनुबंध (कोलैबोरेशन एग्रीमेंट) से दुग्ध उत्पादन में क्रांति आएगी। राज्य सरकार के संकल्प पत्र-2023 में प्रदेश में दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी सहकारी समिति एवं कलेक्शन सेंटर खोले जाने और श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपये के निवेश से प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट एवं चिलिंग सेंटर की संख्या में वृद्धि करने का उल्लेख है। इन संकल्पों को पूरा करने में यह अनुबंध महत्वपूर्ण साबित होगा। यह राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची ब्रांड को मजबूत करेगा।

सांची ब्रांड होगा और अधिक मजबूत

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के सांची ब्रांड को और मजबूत किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित ब्रांड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दुग्ध संघ के प्रबंधन एवं संचालन के लिए प्रबंधन शुल्क और नवीन प्रसंस्करण एवं अधोसंरचनाओं के विकास के लिए भी कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार तकनीकी एवं प्रबंधन विशेषज्ञों को अपने पैरोल पर दुग्ध संघ में पदस्थ किया जाएगा तथा कार्यरत अमले का हित संरक्षण भी किया जाएगा। दुग्ध सहकारी समितियों से संबद्ध डेयरी किसानों की शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी।

दुग्ध उत्पादकों की वार्षिक आय 3500 करोड़ रुपये करना सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रुपये से दोगुनी कर 3500 करोड़ रुपये किए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। प्रदेश में 6 हजार दुग्ध समितियां हैं, जिन्हें बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा, जिससे लगभग 18 हजार गांव कवर किया जा सकेंगे। इससे दुग्ध संकलन भी बढ़कर 20 लाख किलो प्रतिदिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एनडीडीबी द्वारा दुग्ध उत्पादक संस्थाओं (एमपीओ) के माध्यम से कवर किए गए गांवों को 1390 से बढ़ाकर 2590 किया जाएगा तथा दूध की खरीद को 1.3 लाख से बढ़कर 3.7 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में डेयरी प्लांट की क्षमता 18 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

राज्य में गौशालाओं के माध्यम से लिखेंगे गौ-सेवा का नया इतिहास: डॉ. मोहन यादव

सर्वसुविधायुक्त होंगी हाईटेक कामधेनु गौशालाएं

मध्यप्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में राज्य सरकार तेजी से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए गौ शालाओं के विस्तार के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में गौशालाओं के माध्यम से गौ-सेवा का नया इतिहास लिखा जाएगा और नई दुग्ध क्रांति लाई जाएगी।

यह कहना है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का। प्रदेश सरकार गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए जो कदम उठा रही है, उनमें हाईटेक कामधेनु गौशालाओं का निर्माण भी शामिल है। राज्य में इंदौर जिले के महू-मण्डलेश्वर मार्ग पर स्थित आशापुरा और राजधानी भोपाल के बरखेड़ी डोब में अत्याधुनिक गौशालाओं का निर्माण कर रही है। गायों के पालन और संरक्षण के लिए सभी जरूरी सुविधाएं गौशाला में रहेंगी।

भोपाल-इंदौर में 10 हजार गौवंश की क्षमता वाली गौशालाएं

इंदौर जिले की महू तहसील के आशापुरा ग्राम में नगर निगम इंदौर ने कामधेनु गौशाला का निर्माण शुरू किया है। गौशाला के लिए 25 हेक्टेयर भूमि नगर निगम को दी गई है। गौशाला में कुल 10 हजार गौवंश के लिए 8 शेड बनाए जाएंगे। प्रत्येक शेड के साथ में गौवंश के सुगम विचरण के लिए खुला स्थान रहेगा। परिसर में गौवंश के आहार भण्डारण के लिए भूसाघर एवं दानाघर भी बनाए जाएंगे। बीमार गौवंश की देखभाल के लिए विशेष सुविधाओं से युक्त अलग शेड का निर्माण किया जाएगा। हरे चारे की बुआई के लिए खुली कृषि भूमि भी रहेगी। सड़क के दोनों ओर, तालाब के चारों ओर एवं अन्य निर्धारित स्थान पर सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। परिसर में एक गौ पूजन केन्द्र का निर्माण भी किया जाएगा। पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। गोबर से सीएनजी और खाद बनाकर गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, जिससे दुग्ध उत्पादन के साथ-साथ आर्थिक विकास भी हो।

भोपाल जिले के ग्राम बरखेड़ी डोब में 25 एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही हाईटेक गौशाला में एक साथ 10 हजार गौवंश रखे जा सकेंगे। गौशाला में ही चिकित्सा वार्ड भी बनेगा, जहां गौवंशों का इलाज किया जा सकेगा। इसमें सीसीटीवी कैमरों सहित कई आवश्यक संसाधन भी लगाए जाएंगे। गौशाला को बनाने में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी। गौशाला में हरा चारा, भूसा और पशु आहार की सप्लाई के लिए अत्याधुनिक कन्वेयर बेल्ट सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। गौशाला निर्माण के पहले फेज में 2 हजार गायों की क्षमता वाले क्षेत्र का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। गौशाला में गायों के गोबर और मूत्र से जैविक खाद और अन्य सामग्री तैयार करने के लिए यूनिट भी लगाई जाएगी। इस यूनिट में जैविक खाद बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा और बेचा जाएगा। वहीं, घायल और बीमार गायों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सा वार्ड का निर्माण भी किया जाएगा।

D-16009/26